Patrika (Indore), 15th June 2025, Page – 03

#IIT: आइआइटी इंदौर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने की बैठक

मध्यप्रदेश को स्पेसटेक हब बनाने की तैयारी तेज, अगस्त में आएगी नीति

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. मध्यप्रदेश अब स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में प्रदेश को देश का स्पेसटेक इनोवेशन हब बनाया जाए। इसी कड़ी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने आइआइटी इंदौर में एक उच्च स्तरीय नीति परामर्श बैठक आयोजित की, जिसमें 30 से अधिक राष्ट्रीय विशेषज्ञों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक का फोकस 'एमपी स्पेसटेक नीति परामर्श: अवसर और चुनौतियां' था, जिसके माध्यम से प्रदेश की पहली समर्पित स्पेसटेक नीति को अंतिम रूप देने की दिशा में मंथन किया गया। बैठक में देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों और रक्षा

अनुसंधान एजेंसियों के विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें इसरो, डीआरडीओ, आरआरकैट, आइआइटी इंदौर, सी-डॉट, एमसीटीई, देशभर के स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे।

बैठक में राज्य की वैज्ञानिक क्षमता को स्पेसटेक सेक्टर की जरूरतों से जोडने पर जोर दिया गया। आइआइटी इंदौर के निदेशक प्रो. सुहास जोशी ने कहा, स्पेसटेक सिर्फ सैटेलाइट नहीं, यह इंजीनियरिंग, डेटा और इनोवेशन का संगम है। हमारा उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को यहीं अवसर देना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि यह नीति पारंपरिक ढांचे से अलग होकर पारदर्शी और सहभागी तरीके से बनाई जा रही है, जिसमें वैज्ञानिकों, उद्यमियों, शिक्षकों और छात्रों की भूमिका भी शामिल है।

बैठक में जो मुख्य प्रस्ताव सामने आए-

- उज्जैन में ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्लस्टर की स्थापना
- डाटा सेंटर और सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन विकसित करना
- स्वदेशी तकनीकों को प्राथमिकता देना
- साइबर सुरक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर फोकस
- स्टार्टअप्स को सहयोग व स्पेसटेक स्किल डेवलपमेंट पर जोर

अगस्त 2025 में लॉन्च होगी एमपी की पहली स्पेसटेक नीति

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अगस्त 2025 में मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति को सार्वजनिक करेगा। यह नीति न केवल राज्य के युवाओं को नए रोजगार और अनुसंधान के अवसर देगी, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में मध्यप्रदेश की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी।

क्यों है यह नीति अहम?

- मप्र की भू-स्थितियां और शांतिपूर्ण वातावरण अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए उपयुक्त।
- आइआइटी इंदौर जैसे संस्थानों के तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग।
- स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा।
- सुरक्षा, मौसम विज्ञान, रक्षा अनुसंधान में उपयोगी डेटा उपलब्धता।